जेईई (मेन) एवं नीट 2020

युवा परीक्षार्थियों के जीवन और कैरियर दोनों को बचाना जरूरी है।

– हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक

इन दिनों शिक्षा जगत का एक मुद्दा बहुत गर्माया हुआ है। जून, 2020 में होने वाली जेईई (मेन) और नीट 2020 की परीक्षाएँ कोविड के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण स्थगित होती रहीं हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जेईई मेन की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर तक, और नीट 2020 की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होनी है। इन परिक्षाओं को स्थगित कराने के लिये कुछ विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त के अपने फैसले में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की पिटीशन को खारिज कर दिया।

ज्ञातव्य है कि इन दोनों परीक्षाओं का हमारे शिक्षा जगत में बहुत महत्व है क्योंकि जेईई मेन परीक्षा के द्वारा आईआईटी एवं एनआईटी संस्थानों में और नीट के द्वारा प्रतिष्ठित मेडिकल कालेजों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होता है। देश के लाखों मध्यवर्गीय परिवार अपने बच्चों का दाखिला इन नामचीन संस्थानों में हो पाने का सपना देखते हैं, क्योंकि इन संस्थानों में दाखिला होने का मतलब है भविष्य में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा के अवसर प्राप्त होना। आज भारत और भारत के बाहर ऐसे हजारों उद्यमी और सीईओ मिल जायेंगे जो अरबपति बन गये। इनमें ज्यादातर आईआईटी और एनआईटी के पूर्व छात्र रहे हैं। हमारे देश में आईआईटी, एनआईटीए एम्स, आईआईएम आदि ऐसे ब्राण्ड बन गये हैं जिन में पढ़ कर कोई आसमान को चूमने वाली ऊंचाईयों पर पहुंच सकता है।

जेईई (मेन) परीक्षा में 9.53 लाख और नीट 2020 में 15.97 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इन दिनों प्रिंट मीडिया और टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक चल रही बहस का ज्वलंत मुद्दा है कि अगले माह होने वाली ये परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होनी चाहिये या इन्हें फिर से कुछ माह के लिये स्थगित कर दिया जाना चाहिये। दूसरी तरफ एनटीए ने जेईई मेन के प्रवेश–कार्ड जारी कर दिये हैं और नीट 2020 के प्रवेश–कार्ड शीघ्र ही जारी किये जा रहे हैं।

जेईई (मेन) और नीट 2020 की परीक्षाओं को फिर से स्थगित कराने के लिये विद्यार्थियों व` उनके अभिभावको को तर्क है कि कोविड–19 का प्रकोप अपने उभार पर है और रोजाना संक्रमण के 60,000 से 65,000 नये केस आ रहे हैं। कुल संक्रमित लोगों की तादाद भी 31 लाख तक पहुंच गई है। उनका कहना है कि 25 लाख विद्यार्थियों और इतने ही अभिभावकों की जान को खतरा बना रहेगा यदि ये परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाती हैं। परीक्षाओं का विरोध करने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि देश के 11 राज्यों में भयंकर बाढ़ आई हुई है जिसमें एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ऐसी स्थिति में कम से कम ग्यारह राज्यों जैसे बिहार, असम, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र में परीक्षार्थियों का घर से निकल कर परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं होगा।

आज का दौर सौशल मीडिया को दौर है। जेईई (मेन) और नीट 2020 की परीक्षाओं का विरोध करने वाले विद्यार्थियों ने पिछले सप्ताह ट्विटर पर कई हैशटेग बना कर ''पोस्टपोन जीनीट'' अभियान चलाया जिस पर लाखों ट्वीट पोस्ट किये गये। ट्विटर पर लाखों पोस्ट चलाये जायें और हमारे राजनैतिक नेताओं का ध्यान उस पर न जाये, यह नामुमकिन है। परीक्षाओं के स्थगन के समर्थन में अब तक राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सुब्रमह्मणियम स्वामी, स्टालिन और शशि थरूर जैसे राजनीतिज्ञ ट्वीट कर चुके हैं। नवीन पटनायक ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को परीक्षाओं के स्थगन के लिये लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बारे में साझा कार्यवाई के लिये विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। यह तय है कि अगले कुछ दिनों तक इस मुद्दे पर बहुत कुछ राजनैतिक गर्मागर्मी होना बाकी है। स्वीडन की पर्यावरणविद युवानेत्री ग्रेटा थुनबर्ग भी परीक्षा स्थगन को समर्थन दे चुकी हैं।

विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में एक वर्ग ऐसा भी है परीक्षाओं के स्थगन का समर्थन नहीं करता है। उनका कहना है कि कोविड–19 का खतरा तो हाल फिलहाल जाने वाला नही है तो फिर परीक्षाओं को कब तक स्थगित किया जा सकता है? क्या संक्रमण के खतरे से बचने के लिये विद्यार्थियों का कैरियर बरबाद किया जा सकता है? जो परीक्षाएं जून/जुलाई में होती थीं, अगर सितंबर, 2020 में भी होती है तो आईआईटी/एनआईटी व मेडीकल कालेजों का नया सत्र नवंबर, 2020 से पहले शुरू नहीं हो पायेगा। उनका कहना है कि अगर ये परीक्षाएं अगर 2 माह के लिये फिर से स्थगित की जाती हैं तो क्या गारण्टी है कि नवंबर, 2020 तक कोविड की स्थिति बेहतर हो जायेगी?

परीक्षाओं को स्थगित करने या ना करने का मुद्दा बहुत गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 17 अगस्त, 2020 को स्थगन की पिटीशन खारिज करके अपना पल्ला झाड़ लिया है किन्तु केन्द्र सरकार के सामने अगले कुछ दिनों तक एक बड़ी दुविधा रहेगी कि परीक्षाओं के स्थगन की मांग करने वाले बड़े समुदाय के सामने झुककर इस मुद्दे को कुछ समय के लिये टाले या बढ़ते विरोध के बावजूद भी परीक्षाओं को घोषित कार्यक्रमानुसार संचालित करे?

जेईई (मेन) और नीट 2020 की परीक्षाओं को लेकर चल रही रस्साकसी हमारी वर्तमान मनःस्थिति, सोचने के तरीके और भविष्य के प्रति बढ़ रही आशंकाओं का एक लक्षण है जिस कोविड ने पैदा किया है। शायद हम यह तय नहीं कर पा रहे कि कोविड–19 की स्थिति आज ज्यादा खतरनाक है या यह भविष्य में ज्यादा खतरनाक होगी? वैश्विक महामारी ने नीति निर्माताओं, राजनैतिक नेताओं, अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और व्यवसाय जगत के नेताओं को भविष्य के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करने या स्पष्ट पुर्वानुमान लगाने में बेबस या लाचार बना दिया है।

परीक्षाओं के स्थगन की मांग के पीछे भी यही मानसिकता हो सकती हैं कि हम आज के खतरे के प्रति ज्यादा सजग हैं क्योंकि भविष्य के बारे में तो हम अन्दाजा नहीं लगा सकते। स्थगन की मांग करने वाले लोग यही सोचते होंगे कि शायद दो महिने बाद कोविड–19 की स्थिति कुछ बेहतर हो जाये। वे लोग कैरियर और जिन्दगी के बीच दूसरा विकल्प चुन रहे हैं यानी कि उन के लिये कैरियर उतना महत्वपूर्ण नहीं कि जितनी कि जिन्दगी है।

जरा सोचिये कि दुनिया के अन्य देश ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर की बड़ी प्रवेश परीक्षाओं का किस तरह संचालन कर पा रहे हैं? वैसे तो दुनिया के सभी देशों में नामीगरामी संस्थानों में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं होती हैं किन्तु चीन की गाओकाओ परीक्षा के इस वर्ष के अनुभव से कुछ जानकारी मिलती है कि वहां क्या भारत की तरह ही मुश्किलें आई थी और उनका समाधान कैसे ढूढा गया?

इस साल चीन की बहुचर्चित गाओकाओ परीक्षा 8–9 जुलाई को संपन्न हुई थी जिसमें 1 करोड़ 10 लाख परीक्षार्थी बैठे थे। उन दिनों चीन में कोविड की स्थिति भारत की आज की स्थिति से थोड़ी बेहतर थी। फिर भी चीन ने इस परीक्षा के लिये भारी तैयारियां की और विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये थे। चीन ने गाओकाओ के लिये जो उल्लेखनीय तैयारी की वो थी सभी 1 करोड़ 10 लाख

परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य पर परीक्षा तिथियों से दो सप्ताह पूर्व तक नजर रखने के लिये स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त करना। करीब दस लाख परीक्षा निरीक्षकों ने इस परीक्षा को संचालित किया था। चीन में बाकी सब वही तरीके अपनाये गये, जो कि भारत में अपनाये जाने हैं। इस का मतलब है कि कैरियर और जीवन दोनों को बचाते हुए भी परीक्षाएं संचालित करना मुमकिन है।

जरूरी नहीं कि हम जेईई (मेन) और नीट 2020 के प्रसंग में चीन का अनुकरण करें। युवा छात्रों के कैरियर और जीवन को बचाने की दुविधा हमारे सामने खड़ी हुई हैं। हमें दोनो को बचाना जरूरी है किन्तु आज के हालात में कैरियर से ज्यादा जीवन को बचाने की चिंता भी करनी चाहिये। दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई मध्यमार्ग निकालना होगा। फिलहाल केन्द्र सरकार कोई भी फैसला ले उसे जोखिम तो उठानी होगी जिसमें राजनैतिक नफा नुकसान भी देखा जायेगा।